

 सत्यमेव जयते	<b>राजस्थान राजपत्र</b> <b>विशेषांक</b>	<b>RAJASTHAN GAZETTE</b> <b>Extraordinary</b>
	<b>साधिकार प्रकाशित</b>	<b>Published by Authority</b>
	कार्तिक 03, बुधवार, शाके 1945-अक्टूबर 25, 2023 <i>Kartika 03, Wednesday, Saka 1945- October 25, 2023</i>	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

**वित्त (जीएण्डटी) विभाग**

अधिसूचना

**जयपुर, अक्टूबर 25, 2023**

**जी.एस.आर.131 :-**राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956(1956 का अधिनियम संख्या 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.2(1)/एफडी/जीएण्डटी-एसपीएफसी/2017 दिनांक 08-09-2023 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

राज्यपाल के आदेश से,

मनीष माथुर,

संयुक्त शासन सचिव।

**वित्त(जीएण्डटी) विभाग**

अधिसूचना

**जयपुर, सितम्बर 08, 2023**

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 32 के साथ पठित राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 21) की धारा 6 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार की सामाजिक-आर्थिक नीतियों, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के विभागों और उद्यमों के संसाधनों और विशेषज्ञता के उपयोग और उपापन संस्थाओं के व्यक्तिशः बोलियों के आमंत्रण और प्रक्रिया में अपेक्षित समय, धन और प्रयासों की बचत के लिए यह आवश्यक है, इस विभाग की, समय-समय पर यथासंशोधित, अधिसूचना संख्यांक एफ.1(8)/एफडी/जीएण्डटी/2011 दिनांक 04 सितम्बर, 2013 में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

**संशोधन**

उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम संख्यांक 56 के सामने स्तम्भ (2), (3) और (4) में, विद्यमान मद (i) और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“

(i) राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् (राजीविका) के ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा उत्पादित मर्दे	राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् (राजीविका) का ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूह	200000/- रुपये की वार्षिक सीमा के साथ प्रत्येक अवसर पर 25000/- रुपये तक के अध्यक्षीन रहते हुए राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् (राजीविका) के ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूह के उत्पाद, जिनकी दरें राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् (राजीविका) द्वारा यथा अवधारित होंगी, प्रशासनिक विभाग (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग) द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित की जायेंगी।
---	---	---

”

[एफ.2(1)एफडी/जीएण्डटी-एसपीएफसी/2017]

राज्यपाल के आदेश से,

मनीष माथुर,

संयुक्त शासन सचिव।

---

Government Central Press, Jaipur.